1	2		3
36.	परामर्शदायी सेवाएं		
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं		21.78
	प्रबन्ध सेवाएं		9.24
	विपणन		2.61
	निर्माण		4.25
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)		4.04
		योग:	41.92
37.	सेवा क्षेत्र		
	वित्तीय		1488.70
	गैर-वित्तीय सेवाएं		862.87
	बैंकिंग सेवाएं		82.33
	अन्य सेवाएं		13.11
		योग:	2447.01
38.	होटल तथा पर्यटन		
	होटल तथा रेस्तरां		1109.26
	पर्यटन		1.67
		योग:	1110.93
39.	ट्रेडिंग कंपनी		67.86
40.	विविध उद्योग		
	बागवानी		12.56
	कृषि		24.20
	पुष्पखेती		32.32
	अन्य (विविध उद्योग)		720.57
		योग:	789.65
		योग:	27929.16

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

2743. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नया निवेश करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उपक्रमों में आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधी-करण सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए नए सिरे से निवेश का अनुमोदन किया है।

(ग) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपायों में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्य-निष्पादन समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करना, निदेशक मण्डलों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना और उनका व्यवसायीकरण करना, प्रौद्योगिकी उन्नत करना, उत्पाद मिश्र, संयुक्त उद्यमों का अनुमोदन करना इत्यादि शामिल हैं।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण

2744. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारी घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन उद्यमों का निजीकरण करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें लाभकारी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 31-3-1994 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की राज्यवार सूची 22-3-1995 को सभा पटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड-I के परिशिष्ट III में दी गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 117 उद्यमों ने घाटा उठाया है जिसका ब्यौरा सर्वेक्षण के उपर्युक्त खण्ड के विवरण सं॰ 7ख में दिया गया है।

(ख) अब तक इन उद्यमों में से किसी उद्यम के निजीकरण का निर्णय नहीं किया गया है;

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार

एक सतत प्रक्रिया है। सरकार और सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु अपना प्रयास जारी रखे हुए है। इस सम्बन्ध में किए जाने वाले कुछ उपायों में निदेशक मण्डल को अधिकाधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन रुग्ण सरकारी उद्यमों की औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सुपुर्दगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अधिक श्रमशक्ति में कमी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद-मिश्र आदि शामिल है।

Sick units in Uttar Pradesh

2745. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of industrial units that have fallen sick in Uttar Pradesh as on 31st December, 1994;

(b) whether State level panels had been set up to consider the revival of those sick units; and

(c) if so, the details of action initiated by this State level panel so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Data on sick industrial units assisted by banks in the country is compiled by the Reserve Bank of India. According to the latest RBI data, 33722 industrial units in the small scale sector and 144 industrial units in the non-small scale sector were reported sick as at the end of March, 1993, in the state of Uttar Pradesh;

(b) and (c) The Reserve Bank of India has set up State Level Inter-Institutional Committee (SLIIC) under the chairmanship of Secretary, industries Department of the State Government and the local office-in-charge of RBI's Rural Planning and credit Department as convener. The committee periodically meets to discuss and resolve problems of co-ordination between banks and financial institutions, government agencies and other policy issues relating to rehabilitation of sick industrial units in the small scale sector.

Task force to study spurious component production

2746. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Industry has constituted any task force to study the implications of the spurious component production in the country;

(b) whether the Task Force has submitted its report and if so, what are the details;

(c) what is the estimated quantity and value of production and sale of spurious auto components in the country during each of the last three years and so far in 1994-95;

(d) to what extent the production and sale of spurious auto components has affected the genuine manufacturers and also loss to the exchequer by evasion of duty;

(e) to what extent spurious auto component used in the country are responsible for causing more accidents and whether Government have made any survey in this regard; if so, what are the details thereof; and

(f) what steps Government have taken to check the production and sale of spurious components in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) According to a pilot study conducted by the National Council of Applied Economic Research in 1992-93, the market size of spurious components in 1991-92 was of the order of Rs. 2693.35 crores representing 42.23% of the total sale of component during that year. No such study has been conducted thereafter.

(d) According to this study, the total loss of revenue by way of excise duty and